तिब्बत देश

चीन की एशियाई नीति एक गंभीर समस्या।

21 वीं सदी एशिया कि सदी मानी जाती है, जिसमें एक नए विश्व व्यवस्था के प्रभाव से विश्व के मामलों में नई दिश मिलेगी। चीन एशिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए न केवल एशिया में प्रभाव डालना चाहती है, बल्कि पूरे विश्व में भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डालना चाहती है। विश्व शक्ति की अक्ष अब धीरे धीरे एशिया–प्रशांत कि तरफ विकसित होती नज़र आ रहा है।

गत कई वर्षों से चीन अपने ताकत को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु एशिया में भी अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए तैयार कर रहा है जिससे वह दीर्घकालिक रूप से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सके। हालांकि तिब्बत को चीन के अधीन हुए 50 वर्ष से उपर हो चुके हैं और चीन तिब्बत को एक हथियार के रूप में इस्तमाल कर पूरे दक्षिण एशिया के देषों की बुनियादी ढांचा बिगाडने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों के वित्तीय मदद की ज़रूरत का फायदा उठाते हुए एशियाई देशों में अपनी पैठ बनाने लगा है। भारत की विस्तारवादी विदेशी नीतियों के चलते चीन घबराया हुआ है और पूरे एशिया में भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्विंद्वी मानता आया है। चीन की नज़र भारत की हर एक गतिविधियों पर होती है जैसे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हाल में हुए विदेशी यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री के जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, वियतनाम यात्रा की चीन के पीपुल्स डेली में कडी आलोचना हुई और ओबामा की भारत यात्रा को भी चीनी अखबार विस्तारवादी बता रहा है।

इतिहास गवाह है कि पिछले 50 वर्षों में दक्षिण एशिया में चीन एकल बिन्दू एजेंडा के नीतियों का पालन करता आया है। चीन की दक्षिण एशियाई केन्द्र बिन्दू भारत है जिसकी रणनीति एंव राजनीति में अस्थिरता लाकर उसकी प्रमुख शक्तियों के उद्भव को रोकना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी नीति सामरिक और अवसरवादी पहलुओं का मिश्रण है, जो कि सावधानीपूर्वक आकलन किए गए दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। चीन की अन्य एशियाई देशों से संबंध इन दोनों नीतियों का मिश्रण देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुख शक्तियां विशिष्टतापूर्वक उजागर होती है जो कि आने वाले समय में चीन के लिए मुशकिले पैदा कर सकती है। हालांकि चीन भारत की भुगोल एवं संसाधन में कटौती नहीं कर सकता इसलिए दक्षिण एशिया में शक्तियों का संतुलन के राजनेतिक खेल में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरु कर रहा है। चीन द्वारा चुने गए तीन उपायों में शामिल है, (1) पाकिस्तान की सेना का निर्माण, (2) पाकिस्तान को परमाणु हथियारों मिसाइल के राज्य के रूप में उद्भव करवाना, (3) भारत के चारों ओर चीनी उपकरण के ग्राहकों के राज्यों का एक घेरा बनाना जिसे "लाल पट्टी" भी कहते हैं।

दक्षिण एशिया में अपनी सामरिक सहयोगी की रूप में चीन ने पाकिस्तान को चुना और 1960 से लेकर चीन निरंतर पाकिस्तान के सैन्य निर्माण करता आया है और पाकिस्तान के सभी मूल रक्षा उत्पादन के बुनियादी ढ़ांचों का भी निर्माण करता आया है। पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध (जिसे चीन की तरफ से लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल है) एक मजबूत सामरिक कैलकुलस पर आधारित है। यह कैलकुलस भारत को फंसाए रखने के लिए एक दूसरे मोर्चे की उसकी ज़रूरत से बना है। उसकी सामरिक गणना के अनुसार भारत के साथ सैन्य संघर्ष को रोकने की क्षमता इस बात पर निर्भर है कि तिब्बत में एक मजबूत सैन्य क्षमता तैयार किया जाए और परमाणु एवं श्रेणी की क्षेत्र में एक मजबूत पाकिस्तानी सैन्य क्षमता हो। चीन न केवल IRBM पर्वतमाला के साथ "बंध शेल्फ" की सक्षम परमाणु मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान में मिसाइल निर्माण कि सुविधाओं को भी स्थापित कर रहा है। चीनी उद्देश्य यहां पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं में योगदान देना नहीं लेकिन सामरिक रूप से भारत की सुरक्षा को अस्थिर करना है।

चीन की गणना के अनुसार नेपाल एक दोधारी तलवार की तरह है जिसके इस्तमाल से नेपाल की क्षमता को भारत के खिलाफ मजबूत करने हेतु तिब्बत से नेपाल तक सड़क और रेल मार्ग काठमांडू तक पहुंचने का जाल बुनना, वहीं नेपाल के एतिहासिक एवं धार्मिक स्थल लुंबीनी को शेश विकास ज़ोन बनाने के लिए आर्थिक निवेश कि योजना बनाना आदि नेपाल में भारत के प्रभाव का प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ा होना है। कहा जाता है कि गिलगित बाल्तिस्तान श्रेत्र में तकरीबन 10,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। बांगलादेश की बात करें तो भारत के साथ लंबे समय से दोस्ती के बावजूद हाल ही में वहां चीनी निवेश द्वारा तेल एवं गैस उत्खनन के निर्माण के हस्ताक्षर हुए और चटगांव को एक आधुनिक गहन समुद्री बंदरगाह के रूप में उन्नत करने के लिए चीनी सहायता मांगी, जो चीन की एशियाई नीतियों के लिए एक प्रथमिकता है।

तिब्बत के पर्यावरण का दुरूपयोग कर चीन पूर्वी एशिया में बहने वादी नदी ब्रहमपुत्र पर निरभर, कई एशियाई देशों को इस नदी के पानी से वंचित कर रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी चीनी नौसेना का पाया जाना और भारत पाक नियंत्रण रेखा के करीब चीनी सैना की मौजूदगी आदि से यह प्रमाण होता है कि चीन भारत के चारों ओर चीनी उपकरण के ग्राहकों के राज्यों का एक घेरा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलांका, बांग्लादेश, और नेपाल आदि शामिल है। जिन्होंने कुछ समय तक चीन का साथ दिया लेकिन बाद में पीछे हट गए जिससे चीनी रणनीति का सच उजागर होता है। परन्तु म्यांमर को पाकिस्तान की तरह चीन से बड़े पैमाने पर विशेश ध्यान प्राप्त हुआ है। पर कुल मिलाकर यह प्रतीत होता है कि दक्षिण एशिया के छोटे राज्य चीनी कूटनीति को समझ चुके हैं जिसके चलते उन्होंने चीनी रणनीति का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है, बहराल चीन की भारत को घेरने की लाल पट्टी नीति ज्यों–की–त्यों बनी हुई है, जिस पर भारत के लोगों का जागरुक होना बहुत ज़रूरी है।

–तेनज़िन नोरबु

खनन और पर्यटन से तिब्बत का नाजुक पर्यावरण खतरे में

इस भिक्षु के आत्मदाह के तीन माह से भी ज्यादा समय हो गए हैं, लेकिन अभी तक सैकड़ों पुलिस, सेना के जवान और सरकारी अधिकारी मठ को घेरे हुए हैं। चप्पे–चप्पे पर सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं जिससे भिक्षुओं की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है।

(डीपीए, 12 जुलाई)

एक प्रमुख तिब्बती लेखिका ने मंगलवार को अपील की कि एशिया की सबसे पवित्र चोटी कैलाश पर्वत को बेहतर पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान किया जाए और इसे तेजी से वाणिज्यिक पर्यटन केंद्र बनने से रोका जाए। लेखिका सेरिंग वुएजर ने जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए को फोन पर बताया, "मुझे लगता है कि मौजूदा पर्यटन मॉडल ने तिब्बत को नष्ट कर दिया है और उसके पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। वहां दो समस्याएं हैंः खनन और पर्यटन। तिब्बती लोग मानते हैं कि तिब्बत का प्राकृतिक पर्यावरण और वहां के पवित्र पहाड़ खतरे में हैं।"

गौरतलब है कि कैलाश पर्वत तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के सुदुर पश्चिम में है और यह नेपाल एवं भारत से सटी हिमालयी सीमा के करीब है। चीन सरकार ने इस इलाके की सड़कों में सुधार किया है और पिछले साल जुलाई में 6,675 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत के नजदीक एक नए गुंसा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है जहां तिब्बत की राजधानी ल्हासा से हफ्ते में दो उड़ान जाती है। किराया काफी महंगा होने के कारण फिलहाल गुंसा एयरपोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम यात्री कर रहे हैं। सरकार की योजना साल 2020 तक इस एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर सालाना 1,20,000 यात्रियों के लिए करने की है। वुएजर ने एयरपोर्ट के बारे में कहा, "यह कैलाश पर्वत क्षेत्र में भविष्य में पर्यटन के विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित होगा।"

गौरतलब है कि शताब्दियों से केवल कुछ संघर्षशील पर्यटकों को ही सैकड़ों बौद्धों, हिंदुओं, जैनियों और तिब्बती बॉन तीर्थयात्रियों के साथ कैलाश की चढ़ाई का मौका मिला है। पर्यटक आमतौर पर वहां भारत, नेपाल से दुर्गम दर्रों को पार करते हुए या ल्हासा से सड़क मार्ग से आते हैं। चीन सरकार कैलाश और उसके पास स्थित मानसरोवर झील के आसपास के इलाके में एक नया पवित्र झील दर्शन क्षेत्र तैयार करना चाहती है और एयरपोर्ट का विस्तार भी इसी योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत ल्हासा से इस इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को उन्नत बनाया जाएगा और कैलाश के निकट होटलों एवं रेस्टोरेंट्स का विकास किया जाएगा। इस पर्वत के इर्दगिर्द परिक्रमा पथ पर 57 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय दौड़ का आयोजन अगस्त में किया जा रहा है जिसमें 15 टीमें और सरकारी टेलीविजन के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। वुएजर ने इस हफ्ते अपने ब्लॉग पर इस रेस और सरकार की विकास योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "कृपया इस पवित्र पर्वत और झील को व्यावसायिक विकास के लिए इस्तेमाल करना बंद करें।"

सरकार ने साल 2008 में ल्हासा में चीनी शासन के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही तिब्बत में कई बार विदेशियों के पर्यटन पर रोक लगाई है या उसे सीमित किया है। लेकिन कैलाश और तिब्बत के अन्य इलाकों में पर्यटकों की संख्या में अब भी इजाफा होता दिख रहा है, लेकिन इसकी वजह वहां तेजी से बढ़ती घरेलू चीनी पर्यटकों की संख्या है। चीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि तिब्बत में पिछले साल 60 लाख पर्यटक आए और इस साल वहां 75 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान है। साल 2020 तक यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है।

पर्यटकों की संख्या में अचानक तेजी से बढ़त की वजह है साल 2006 में ल्हासा को पहली बार रेल मार्ग से जोड़ना। चीन ने कई तिब्बती क्षेत्रों को बड़े पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया है जैसे ल्हासा और यून्नान प्रांत का आधिकारिक सांग्री–ला पर्यटन कस्बा।

कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उसने चीन के संपन्न शहरों से पर्यटकों को यहां लाकर यहां के गरीबों और इन सुदुर क्षेत्रों की आर्थिक दशा को बदल दिया है। लेकिन निर्वासित तिब्बतियों के समर्थकों का कहना है कि इस विकास से काफी हद तक चीन के हान नस्ल की बहुसंख्यक जनता का फायदा हो रहा है और यह तिब्बती संस्कृति एवं धर्म पर भद्दा कचरा ही फैलाता है। इसके पहले एक इंटरव्यू में वुएजर ने कहा था कि चीनी लोगों में तिब्बत के लिए जगा नया प्रेम ऐसे ही है जैसे कोई 'अपने पालतू जानवर से प्रेम' करता है।

चीन ने तीन तिब्बती काउंटी में निगरानी बढ़ाई

(रेडियो फ्री एशिया, 13 जुलाई)

सिचुआन प्रांत के तीन तिब्बती काउंटी में चीनी अधिकारियों ने निगरानी और विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेने की घटनाएं बढ़ा दी हैं। कार्डजे प्रशासनिक क्षेत्र के देंगे, ताउ और कार्डजे काउंटी के तिब्बतियों ने हाल के हफ्तों में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं जिनमें तिब्बत की आज़ादी का आह्वान किया गया और अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस आने देने की मांग की गई। अपना नाम न छापने की शर्त पर देगे काउंटी के एक निवासी ने बताया कि पुलिस ने मार्च में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में हाल में एक तिब्बती को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया, "देगे काउंटी के जातोए क्षेत्र में तीन तिब्बतियों ने आज़ादी समर्थक पोस्टर लगाए थे, जिसमें से एक को जून माह में चीनी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है।" उन्होंने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनकारियों के नाम जम्पा कोनछोग, सेरिंग क्यिपो और लो थुबटेन है। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कई स्थानीय सरकार की इमारतों, पुलिस थानों के दरवाजों और खिड़कियों पर पोस्टर लगाए थे। सूत्र ने बताया, "उन्होंने ऐसे कई विरोध पत्रक वितरित किए जिनमें दलाई लामा की वापसी और तिब्बत को आज़ाद करने की मांग की गई थी। इन पत्रकों और पोस्टरों पर उन्होंने साफ तौर पर

अपना नाम भी छपवाया था।" उन्होंने कहा, "करीब 10 दिनों तक कई सौ सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बल इन तीनों लोगों की तलाश में लगे रहे। जब इसके बावजूद वे तीनों को नहीं ढूंढ पाए तो तीनों के परिवार के एक–एक सदस्य को उठा लिया गया और उन्हें तीन महीने तक कैद रखा गया। इसके बाद जून में किसी दिन देगे काउंटी पुलिस सेरिंग किपो को गिरफ्तार कर पाई।"

देगे के एक और नागरिक ने सेरिंग किपो की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "उनको इस साल जून में करीब एक माह पहले गिरफ्तार किया गया। तबसे किसी को यह नहीं पता है कि वह कहां हैं और उन्हें कैसे रखा गया है। कई लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को किपो को उन स्थानों पर ले जाते देखा है जहां विरोध प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा जम्पा कोनछोग और लो थुबटेन का भी कोई पता नहीं है।" दक्षिण भारत के एक निर्वासित तिब्बती गेशे लोबसांग फुंत्सोग ने बताया कि सिचुआन प्रांत की पुलिस ने उन तिब्बतियों को भी परेशान किया जो दलाई लामा के 76वें जन्म दिन समारोह पर 6 जुलाई को अगरबत्तियां जला रहे थे। उन्होंने बताया, "ताउ में कई तिब्बतियों ने दलाई लामा का जन्म दिन मनाया। लेकिन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के उत्सव कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रशासन ने न्यासा दार्गेलिंग मठ और दो स्थानीय ननरी की बिजली काट दी। इसके अलावा भिक्षुओं और भिक्षुणियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकारी अधिकारियों ने मठों के अंदर ही डेरा डाल लिया।" कार्डजे काउंटी से फोन करने वाले एक तिब्बती नागरिक ने बताया कि उसने यह देखा है कि सुरक्षा कर्मी एक युवा तिब्बती को पकड़ कर काउंटी कार्यालय ले जा रहे थे, जहां हाल के हफ्तों में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इस नागरिक ने बताया, "7 जुलाई को मैं एक कार्डजे कस्बे की एक चाय की दुकान में चाय पी रहा था, तभी मैंने काफी शोरगुल सुना। जब मैं कई अन्य लोगों के साथ भीड़ की तरफ गया तो मैंने देखा कि एक युवा तिब्बती को पुलिस के जवान खींच के ले जा रहे हैं और उसे एक पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बैठाते हुए उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा था और गाड़ी में बैठ जाने के बाद भी पुलिस ने उसे लोहे के रॉड एवं छड़ी से पीटना जारी रखा। वह करीब 20 साल का लड़का था। मैं नहीं समझता कि वह देर तक अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने में सक्षम रहा होगा।" कार्डजे में रहने वाले एक अन्य तिब्बती नागरिक ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा कि गिरफ्तार युवक की पहचान के बारे में बहुत कम विवरण मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, "स्थानीय तिब्बती गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में जानकारी देने से काफी हिचकते हैं। गिरफ्तार प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों से घिरा हुआ था। मैंने देखा कि सेना के जवान प्रमुख चौराहों पर जांच बिंदु बनाकर उस इलाके से गुजरने वाले सभी लोगों की जांच कर रहे थे। पूरे कस्बे में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं।" भारत में निर्वासन में रहने वाले एक तिब्बती के अनुसार क्विंघई प्रांत के युशु प्रशासनिक क्षेत्र के चीनी अधिकारियों ने गत 12 जुलाई को नांगचेन काउंटी में आधिकारिक उत्सव मनाने की योजना का विरोध कर रहे आठ भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया, "आठों भिक्षु जुरमांग मठ से जुड़े हैं और उन्होंने ऐसे पत्रक वितरित किए जिसमें तिब्बतियों से यह आह्वान किया गया था कि वे सरकारी उत्सवों में भाग न लें जैसे सरकार प्रायोजित घुड़दौड़ और गीत एवं नृत्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां। उन्होंने कहा कि भूकंप जैसी दैवी आपदा में लोगों के मारे जाने की वजह से उत्सव मनाने की कोई वजह नहीं है।" गौरतलब है कि युशु काउंटी में अप्रैल 2010 में एक विनाशकारी भूकंप आया था जिससे जेकुंडो नाम का तिब्बती कस्बा पूरी तरह से नष्ट हो हो गया था। इस आपदा में इस बस्ती और इसके आसपास के करीब 3000 लोग मारे गए थे।निर्वासित तिब्बती ने बताया, "विरोध प्रदर्शन में भिक्षुओं के शामिल होने की शंका में पुलिस का एक जत्था 12 जुलाई की रात जुरमांग मठ में घुस गया और उन्होंने आठ भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया।" चीनी शासन के खिलाफ कई हफ्तों की अशांति के बाद सिचुआन और क्विंघई प्रांत के तिब्बती जनसंख्या वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई बढ़ गई है। गत 6 जून को शुरू विरोध प्रदर्शन 17 जून तक काफी बढ़ गए और इसके बाद कार्डजे प्रशासन ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। निर्वासित तिब्बती सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग लामा या स्थानीय तिब्बती नागरिक थे। तिब्बत की आज़ादी की मांग करने के अलावा विरोध प्रदर्शनकारी यह भी मांग कर रहे थे कि उन राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए जिन्हें पिछले साल कार्डजे में गिरफ्तार किया गया था। उधर, सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक क्षेत्र कीर्ति मठ की चीनी सुरक्षा कर्मियों द्वारा तब से घेराबंदी जारी है जब वहां 16 मार्च को एक युवा भिक्षु ने चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह कर लिया। इस भिक्षु के आत्मदाह के तीन माह से भी ज्यादा समय हो गए हैं, लेकिन अभी तक सैकड़ों पुलिस, सेना के जवान और सरकारी अधिकारी मठ को घेरे हुए हैं। चप्पे–चप्पे पर सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं जिससे भिक्षुओं की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है।

"कुछ साल पहले चीन सरकार पंचेन लामा को लाबरांग लेकर आई थी, लेकिन स्थानीय लोग उनके स्वागत समारोह में जाने को तैयार नहीं हुए। इस साल भी बहुत से तिब्बती नागरिक यह कह रहे हैं कि वे चीनी पंचेन लामा के स्वागत के लिए नहीं आ सकते।"

तिब्बत में गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 21 जुलाई)

तिब्बत के नागछू काउंटी के देक्यी टाउनशिप के झाबतेन मठ से 6 जुलाई को 22 साल के एक भिक्षु दोर्गे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोर्गे का 'जुर्म' यह था कि वे वृक्षों, बिजली के खंभों आदि पर आनुष्ठानिक तिब्बती पताका लगा रहे थे और अपनी कार में ऐसे

उन्होंने कहा कि सिंधु डेल्टा का करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर इलाका महासागर में समा चुका है और सिंधु नदी पर बनने वाले बांधों की वजह से इस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, यदि पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर दाइमर और कालाबाग बांध बनाए तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है।

1500 से 2000 झंडियां—पताके लेकर यात्रा कर रहे थे। भारत स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने गत 16 जुलाई को यह जानकारी दी। टीसीएचआरडी ने कहा कि दलाई लामा के 76वें जन्मदिन पर दोर्गे तिब्बत में जगह—जगह पताके लहरा रहे थे। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि दोर्गे कहां हैं। उनके साथ कार में सवार एक स्कूली छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।इसके अलावा गत 12 जुलाई को सिचुआन प्रांत के कार्डजे काउंटी स्थित नॉर्जिन गांव की दो लड़कियों 16 साल की टाशी पालमो और 19 साल की पेमा यांगजोम की चीनी पुलिस ने जमकर पिटाई की है। कार्डजे मिडल स्कूल की इन दोनों छात्राओं ने काउंटी के बाजार में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इन दोनों की हालत गंभीर है। खबर है कि इन दोनों लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान तिब्बत की आज़ादी और दलाई लामा की वापसी के समर्थन में नारे लगाए।

कर्नाटक की तिब्बती बस्ती बयालकुप्पी के सेरा जे तेहोर खांगस्तेन के एक भिक्षु लोबसांग ढोनधुप के हवाले से फायूल डॉट कॉम ने गत 18 जुलाई को खबर दी है कि स्थानीय निवासियों ने इन दोनों लड़कियों को पुलिस द्वारा पीटे जाते देखा है और गंभीर हालत के बावजूद उनका इलाज भी नहीं कराने दिया गया।

इसके अलावा एक अन्य घटना में गत 15 जुलाई को सिचुआन प्रांत के मुख्य कार्डजे टाउन में कई अन्य लोगों के साथ 34 साल के गवांग फुंत्सोक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। ये सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और चीनी शासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। निर्वासित तिब्बती प्रशासन के वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट ने 20 जुलाई को यह जानकारी दी। इस खबर के अनुसार गत 10 जुलाई को कार्जे के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे 23 साल के सामफेल धोनढुप और 17 साल के लोबसांग ल्हुनढुप और कई अन्य तिब्बती युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई।टीसीएचआरडी ने 21 जुलाई को खबर दी है कि पूर्वी तिब्बत के नाबा क्षेत्र में स्थित कीर्ति मठ के दो भिक्षुओं को गत 15 जुलाई को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 39 साल के लोबसांग खेढुप को 4 मई को मठ से गिरफ्तार किया गया था और 36 साल के लोबसांग ग्यात्सो को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को कोर्ट में पेश करने से पहले करीब दो महीने तक अज्ञात स्थान पर रखा गया था और किसी को भी उनसे संपर्क नहीं करने दिया गया। भारत में रहने वाले तिब्बती सूत्रों के हवाले से फायूल डॉट कॉम ने खबर दी है नाबा क्षेत्र के कीर्ति मठ के 34 साल के भिक्षु धोनयो दोरजी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोरजी को गत 8 अप्रैल को मठ से गिरफ्तार किया गया था और तब से कोर्ट में पेश करने तक उनको अज्ञात स्थान पर रखा गया था।

अपने पंचेन लामा को वैधता दिलाने के लिए जूझ रहा है चीन

(रेडियो फ्री एशिया, 29 जुलाई)

अपने चुने हुए पंचेन लामा को तिब्बतियों के ऊपर थोप कर उन्हें स्वीकार्य बनाने में चीन विफल रहा है। चीन ने तिब्बतियों की बहुलता वाले एक क्षेत्र में इस माह अपने द्वारा चयनित दलाई लामा को मंच पर लाने का निर्णय लिया था, लेकिन लोगों के बीच बढ़ रहे असंतोष को देखते हुए चीन सरकार ने इस विवादास्पद निर्णय को वापस ले लिया। सूत्रों के अनुसार गांसू प्रांत के कान्हलो तिब्बत स्वायत्तशासी प्रशासन में स्थित सांगछू काउंटी के लाबरांग मठ में हाल में 21 साल के गेनकेन नोर्बू के दौरे से पूर्व भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। लाबरांग क्षेत्र में रहने वाले एक तिब्बती नागरिक ने बताया कि आम तिब्बती लोग और भिक्षु ने नोर्बू के दौरे की खबर सुनकर काफी नाराज थे। तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था लाबरांग मठ में साल 2008 में चीनी शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सूत्र ने कहा, "उनके 20 से 30 जुलाई के बीच आने की संभावना थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वे अगस्त या सितंबर में किसी समय आ सकते हैं। स्थानीय तिब्बतियों (आम तिब्बती और लाबरांग मठ के भिक्षुओं) में फैले व्यापक असंतोष को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनके आने की तैयारियों पर रोक लगा दी गई है।" सूत्रों ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में तैनात तिब्बती कर्मचारी इस दौरे में सहयोग करने को तैयार नहीं है, जबकि चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर नोर्बू के स्वागत के लिए कर्मचारी तैयार नहीं हुए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनका वेतन काट लिया जाएगा।

सूत्र ने कहा, "चीनी अधिकारियों ने सांगछू काउंटी कार्यालय के तिब्बती कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे नोर्बू का उत्साह के साथ स्वागत करें और उन्हें खाता भेंट करें और साष्टांग प्रणाम करें। बहुत से लोग ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, जिस पर अधिकारियों ने धमकी दी है कि यदि वे स्वागत समारोह में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी।" चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए गेनकेन नोर्बू को आधिकारिक चेहरा स्वीकार करने में तिब्बतियों को राजी करने में चीनी अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। दलाई लामा द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सर्वोच्च भिक्षु के अवतार के रूप में छह साल के बालक गेदुन छोक्यी निमा के पहचान के बाद इसके प्रतिकार के रूप में 1995 में चीन ने नोर्बू को अपनी तरफ से पंचेन लामा घोषित किया। दलाई लामा ने जिस बालक का चुनाव किया था, वह इस घोषणा के बाद से ही परिवार सहित गायब हो गया और तबसे उनका कोई पता नहीं है। ज्यादातर तिब्बती मानते हैं कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें कैद कर रखा है। लाबरांग के पास रहने वाली एक तिब्बती महिला ने कहा,"चीनी अधिकारी स्थानीय तिब्बतियों से

कह रहे हैं कि पंचेन लामा के पहुंचने पर वे उनका स्वागत करें।" उन्होंने कहा, "कुछ साल पहले चीन सरकार पंचेन लामा को लाबरांग लेकर आई थी, लेकिन स्थानीय लोग उनके स्वागत समारोह में जाने को तैयार नहीं हुए। इस साल भी बहुत से तिब्बती नागरिक यह कह रहे हैं कि वे चीनी पंचेन लामा के स्वागत के लिए नहीं आ सकते।" उन्होंने बताया कि पंचेन लामा के दौरे की तैयारी चल रही है और 1,000 से ज्यादा चीनी पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवान यहां तैनात हैं और बहुत से जवान सादे कपड़ों में भी दिख रहे हैं।

'गिलगित–बाल्तिस्तान को जल्द ही तिब्बत में मिला लेगा चीन'

(27 जुलाई)
हेनरी एल. स्टिमसन सेंटर के इंस्टीट्यूट फॉर गिलगित बाल्तिस्तान स्टडीज और फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बाल्तिस्तान ने संयुक्त रूप से 27 जुलाई को वाशिंगटन डी.सी. में एक कार्यक्रम "दुनिया की छत पर संसाधनः अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं वृहत हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टिमसन सेंटर के डॉ. डेविड माइकल ने की। इस कार्यक्रम के वक्ताओं में इंडियाना यूनिवर्सिटी के डॉ. सुमित गांगुली, स्टिमसन सेंटर के डॉ. इकबाल हसनैन, एमईएमआरआई के तुफैल अहमद, ईएसआई के माइकल पेंडर्स और आईजीबीएस के सेंगे सेरिंग शामिल थे। डेविड माइकल ने भोजन और चारे की बढ़ती मांग के बारे में बात की जिससे हिमालयी क्षेत्र में जल का उपभोग बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंधु डेल्टा का करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर इलाका महासागर में समा चुका है और सिंधु नदी पर बनने वाले बांधों की वजह से इस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, यदि पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर दाइमर और कालाबाग बांध बनाए तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है।
तुफैल अहमद ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह से एशिया में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं,पाकिस्तान और चीन अपना प्रभाव ईरान, अफगानिस्तान और अन्य एशियाई देशों में बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी और चीन का उभार ऐसे दो मुख्य वाहक हैं जो अगले सालों में पाकिस्तान के सैन्य और आर्थिक हितों का निर्धारण करेंगे।उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की कि गिलगित–बाल्तिस्तान में चीन लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। डॉ. हसनैन ने कहा कि डेढ़ अरब से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष तौर पर तिब्बत पठार के जल संसाधनों पर निर्भर हैं जो कि चिंताजनक तेजी से खत्म हो रहे हैं।उन्होंने सियाचिन और खुंजेराब ग्लेशियर का उदाहरण दिया जो कि अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान प्रभावित होगा क्योंकि उसकी 78 फीसदी जनसंख्या सिंधु नदी तंत्र पर ही निर्भर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में जल समस्याओं का कोई टिकाऊ हल चीन को साथ लिए बिना नहीं हो सकता। डायमर बांध पर विवाद की चर्चा करते हुए डॉ. हसनैन ने कहा कि यह बांध भूकंप संभावित क्षेत्र में है और इससे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों का जीवन लगातार खतरे में बना हुआ है। माइकल पेंडर्स ने गिलगित–बाल्तिस्तान के लोगों के स्वशासन की मांग का समर्थन किया और इस इलाके में चीन की उपस्थिति को गैरकानूनी तथा इसे वहां के सतत विकास की परंपरा के लिए एक चुनौती बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गिलगित–बाल्तिस्तान जैसे विवादित क्षेत्र में बांध नहीं बनाए जाने चाहिए और इसे उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौतों से सुरक्षा मिलनी चाहिए जैसा कि अन्य विवादित क्षेत्रों को हासिल है। अट्टाबाद झील आपदा (जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए) का संदर्भ देते हुए माइकल पेंडर्स ने आह्वान किया कि ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहायता दी जानी चाहिए।
डॉ. गांगुली ने कहा कि चीन और दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास के कई प्रस्तावक ये भी हैं कि उन्होंने अपने दीर्घकालिक पर्यावरणीय नतीजों की पूरी तरह से अवहेलना की है और संसाधनों के उपभोग की उनकी भूख से पारिस्थितिकी तंत्र को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। गिलगित–बाल्तिस्तान के हालात की चर्चा करते हुए डॉ. गांगुली ने कहा कि स्थानीय लोगों की रजामंदी के बिना पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक इस इलाके में संसाधनों का दोहन जारी है और इस पर किसी की नजर नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा पर चलने वाली गतिविधियों पर केंद्रित हैं। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा कि भारत के तेजी से तरक्की करने की वजह से चीन में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और इसकी वजह से चीन की गिलगित–बाल्तिस्तान में रुचि बढ़ती जा रही है।
सेंगे सेरिंग ने चीन द्वारा बांध निर्माण और गिलगित–बाल्तिस्तान खनिज संसाधनों के दोहन से जुड़े सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाई गई गिलगित–बाल्तिस्तान परिषद चीन के साम्राज्यवाद को सहयोग देने के लिए ही है।उन्होंने कहा कि इलाके में यदि चीन के अवांछित उपस्थिति को चुनौती नहीं दी गई तो गिलगित–बाल्तिस्तान का भविष्य भी तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान जैसा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमालयी क्षेत्र के देशज लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब किफायती संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा की जाए और संयुक्त राष्ट्र गिलगित–बाल्तिस्तान में

इस उद्देश्य के साथ ही चीन तिब्बत से नेपाल तक सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछाने में लगा हुआ है और प्रचंड के नेतृत्व वाले माओवादियों के साथ गहरे रिश्ते कायम कर रहा है और उनके काडर के साथ भी जो नेपाली सेना में मिल जाना चाहते हैं।

मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने में सहयोग करे।

दक्षिण एशिया में चीन के सामरिक इरादे

(श्रीलंका गार्डियन, 12 जुलाई)

बी. रमण

इन सबसे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्लिंटन किस तरह से चीन–पाकिस्तान गठजोड़ से निपटेंगी, ऐसे समय में जबकि नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका धीरे–धीरे चीन के पंजे में फंस रहे हैं।

चीन कोई दक्षिण एशियाई ताकत नहीं है, लेकिन वह अपने को दक्षिण एशिया में मजबूत उपस्थिति के लिए तैयार करना चाहता है ताकि दीर्घकालिक रूप से उसकी सामरिक जरूरतों की पूर्ति हो सके। दक्षिण एशियाई देशों की बुनियादी ढांचा विकास की भूख, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वित्तीय मदद की जरूरत का फायदा उठाते हुए चीन ने इन देशों में अपनी पैठ बना ली है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी नीति सामरिक और अवसरवादी पहलुओं का मिश्रण है,जो कि सावधानीपूर्वक आकलन किए गए दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है और इसके रास्ते में आने वाले अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के अवसरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के साथ इसके संबंधों के मामले में सामरिक पहलू देख सकता है। यही नहीं अन्य एशियाई देशों के साथ उसके संबंधों में इन दोनों का मिश्रण देखा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ इसके संबंध (जिसे चीन की तरफ से लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल है) एक मजबूत सामरिक कैलकुलस पर आधारित हैं। यह कैलकुलस भारत को फंसाए रखने के लिए एक दूसरे मोर्चे की उसकी जरूरत से बना है। उसकी सामरिक गणना के अनुसार भारत के साथ सैन्य संघर्ष रोकने की क्षमता इस बात पर निर्भर है कि तिब्बत में मजबूत सैन्य क्षमता तैयार किया जाए और परमाणु एवं परंपरागत क्षेत्र में एक मजबूत पाकिस्तानी सैन्य क्षमता हो। यही सब वह करने की कोशिश कर रहा है।वह यह देखने की कोशिश कर रहा है कि आपूर्ति वाहनों सहित समूचे सैन्य क्षमता में भारत के मुकाबले पाकिस्तान बेहतर हो। वह पाकिस्तान की आक्रमण और प्रतिरक्षा वायु एवं नौसेना क्षमता को मजबूत करने में लगा है।गत 2 मई, 2011 को ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नौसैनिक कमांडो दस्ते द्वारा एबॅटाबाद पर हुई कार्रवाई के बाद चीन ने वायदा किया कि वह पाकिस्तान की वायु सेना क्षमता को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी वायु सेना की जरूरत के लिए विमानों की आपूर्ति तेज करेगा। इसके साथ ही, वह काराकोरम राजमार्ग मरम्मत और सुधार में मदद मर कर रहा है और उसने अन्य सड़कों के निर्माण में भी मदद करने का आश्वासन दिया है। सीक्यांग से गिलगित–बाल्तिस्तान होते हुए एक रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए एक संभाव्यता अध्ययन किया जा रहा है। चीन को पाकिस्तान से बुनियादी ढांचा विकास के कई प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन वह गिलगित–बाल्तिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता और बलोचिस्तान से जुड़ी परियोजनाओं को सबसे कम प्राथमिकता दे रहा है। उसने ग्वादर वाणिज्यिक बंदरगाह के समयबद्ध रूप से उन्नतीकरण में रुचि नहीं दिखाई है। इस बंदरगाह का निर्माण एक नौसैनिक केंद्र में चीन की सहायता से ही किया गया है। इसी प्रकार वह ग्वादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और ग्वादर से सीक्यांग तक तेल–गैस पाइपलाइन निर्माण जैसे अन्य पाकिस्तानी प्रस्तावों पर भी काफी धीमे गति से काम कर रहा है।गिलगित–बाल्तिस्तान क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चीन द्वारा प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि वह इस इलाके में किसी भी संभावित भारतीय खतरे से पाकिस्तान को बचाव में सक्षम बनाना चाहता है और पाकिस्तानी सैन्य बलों को ऐसी क्षमता देना चाहता है जिससे वे भारत के लिए एक भरोसेमंद खतरा बन सकें जिससे चीन की सामरिक लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सके।

एक अमेरिकी पत्रकार ने अपुष्ट खबर दी है कि गिलगित–बाल्तिस्तान क्षेत्र में करीब 10,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। यदि यह खबर सच है तो इससे पाकिस्तान में चीन के सामरिक लक्ष्यों की पुष्टि होती है।एबॅटाबाद की घटना के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादी विरोधी रुख का मुखर रूप से बचाव किया है और वह यह प्रयास कर रहा है कि अब पाकिस्तान को कोई नुकसान न होने पाए क्योंकि ओसामा बिन लादेन को पांच साल तक एबॅटाबाद में शरण देने की संभावित पाकिस्तानी जटिलता (सरकारी या गैर सरकारी) के बाद अमेरिका उसे संदेह की नजर से देख रहा है। इस प्रकार चीन का सामरिक हित इस बात में है कि पाकिस्तान की रक्षा करे, उसकी क्षमता को मजबूत करे और जरूरत के समय उसके द्वारा भारत के लिए खतरा बन सकने की प्रभावशीलता को बनाए रखे। उसकी यह रणनीति जारी रहेगी भले ही भारत के चीन या पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार आ जाएं।

चीन की सामरिक गणना में पाकिस्तान के बाद नेपाल को दूसरी प्राथमिकता हासिल है। चीन के सामिरिक चिंतकों एवं नियोजकों के लिए नेपाल का महत्व सिर्फ युद्ध या शांति के समय भारत के खिलाफ उसके इस्तेमाल की संभावना से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि उसे लगता है कि परमपावन दलाई लामा की मौत के बाद यदि माहौल खराब होता है तो नेपाल का इस्तेमाल भारत तिब्बत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर सकता है। चीन की गणना के अनुसार नेपाल एक दोधारी तलवार बन सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नेपाल की क्षमता को किस तरह से मजबूत किया जाए? इस उद्देश्य के साथ ही चीन तिब्बत से नेपाल तक सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछाने में लगा हुआ है और प्रचंड के नेतृत्व वाले माओवादियों के साथ गहरे रिश्ते कायम कर रहा है और उनके काडर के साथ भी जो नेपाली सेना में मिल जाना चाहते हैं। माओवादियों के सत्ता में होने का लाभ उठाते हुए नेपाल में चीन के

राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव को मजबूत करना पेइचिंग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दोनों देशों के बीच सैन्य–सैन्य संबंध साल 1998 से ही सबकी नजर में चढ़ रहा है जब नेपाली सेना ने अपने अधिकारियों एवं सैनिकों को चीनी सैन्य विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया था। अकादमिक साल 2006–07 में नेपाली सेना के 21 अधिकारी और सैनिक प्रशिक्षण के लिए चीन भेजे गए। चीन ने साल 2002 में नेपाली सेना द्वारा आयोजित एडवेंचर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपने सैन्य अधिकारियों को भेजा। चीन पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वह नेपाल को दक्षिण एशिया तक पहुंच के लिए रास्ता बनाना चाहता है और इसीलिए तिब्बत से नेपाल तक सड़क मार्ग का विकास किया जा रहा है और ल्हासा रेल मार्ग का विस्तार काठमांडू तक किया जा रहा है। चीन यदि इन विचारों पर अमल करने में सफल होता है तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा।भारत अपने को नेपाल में कुछ ऐसी ही स्थिति में पा रहा है जैसा कि उसे म्यांमार मे ंदेखना पड़ रहा है, हर समय उसे यहां राजनीतिक एवं आर्थिक फायदो के लिए चीन से मुकाबला करना पड़ता है।

अब तक भारत का नेपाल के सामरिक खेल के मैदान में लगभग एकाधिकार रहा है। अब वहां दूसरा खिलाड़ी चीन आ चुका है। म्यांमार में पूर्व सैन्य सरकार को जब भी भारत या चीन के हित में से चुनाव करना होता, वह हमेशा चीनी हित का चुनाव करती क्योंकि वह चीन से डरती थी और वह चीन के प्रति इस कृतज्ञता से दबी हुई थी कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्व सैन्य जुंटा सरकार का समर्थन किया था।नेपाल में जब भी भारत एवं चीन के हितों में टकराव की बात आती है माओवादी प्रभाव वाली सरकार चीनी हितों का चुनाव कर सकती है,किसी डर या कृतज्ञता की वजह से नहीं बल्कि विचारधारात्मक जुड़ाव की वजह से। चीन के लिए तीसरी प्राथमिकता बांग्लादेश है।भारत के साथ अपनी लंबे समय से दोस्ती के बाजवूद प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पूववर्ती बेगम खालिदा जिया की पूरब की ओर देखो नीति को जारी रखे हुए हैं और चीन के साथ संबंधों को मजबूत किया है। उनकी चीन यात्रा के दौरान एक चीनी कंपनी के साथ बांग्लादेश में तेल एवं गैस उत्खनन के लिए हस्ताक्षर हुए। उन्होंने चटगांव को एक आधुनिक गहन समुद्री बंदरगाह के रूप में उन्नत करने के लिए चीनी सहायता मांगी। उनकी सरकार ने भारतीय चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए यह दोहराया कि भारत को हमेशा चीन की सहायता से उन्नत चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत होगी। कम से कम श्रीलंका एवं म्यांमार कुछ हद तक भारत एवं चीन को बराबर के पलड़े पर रख रहे हैं, उसे तेल एवं गैस उत्खनन का बराबर का मौका देकर, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर इस बात का भारी विरोध है कि भारत को वहां के ऊर्जा संसाधनों के विकास का मौका दिया जाए।

चीन ने भारत को घेरा

(द डिप्लोमैट, 21 जुलाई)

पिछले कुछ महीने अमेरिका–पाकिस्तान संबंधों के लिए खटास वाले रहे हैं और हाल में अमेरिका द्वारा 80 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता पर रोक लगाने से संबंध और भी नाजुक हो गए। अब जबकि पाकिस्तान कहीं और से सहयोग की तलाश में है, यह अपरिहार्य लगता है कि चीन इस मौके का फायदा उठाए। इन सबसे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्लिंटन किस तरह से चीन–पाकिस्तान गठजोड़ से निपटेंगी, ऐसे समय में जबकि नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका धीरे–धीरे चीन के पंजे में फंस रहे हैं।

लेकिन अगर पाकिस्तान को सहायता रोकने के अमेरिकी निर्णय पर विचार करें तो क्या इसे एक सामरिक गलती कही जाएगी जिसने पाकिस्तान को चीन की तरफ जाने को मजबूर किया है।घरेलू राजनीतिक संदर्भ से अमेरिका जब बजट के मोर्चे पर दलगत राजनीति में उलझा हुआ है,ओबामा प्रशासन के सामने विकल्प बहुत कम था। अमेरिकी कर दाता अब नहीं चाहते कि उनका पैसा एक ऐसी सरकार को दिया जाए जो अक्षम और ढोंगी साबित हुई है। यह खुलासा कि ओसामा बिन लादेन इतने लंबे समय तक पाकिस्तान में पनाह लेता रहा, शायद अंतिम कड़ी साबित हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के लिहाज से देखें तो वह सहायता रोकने के इस कदम को ऐसे समय में अपमान के रूप में ही लेंगे, जब वे वजीरिस्तान में ऐसी खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे बहुत से पाकिस्तानी 'अमेरिका का युद्ध' मानते हैं।चीन के सामने ऐसा कोई घरेलू दबाव (या आर्थिक मुश्किल) नहीं है जैसा कि अमेरिका के सामने है। इसलिए वह रोते पाकिस्तान को अपने कंधे का सहारा दे सकता है। जैसा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है, 'चीन सदाबहार दोस्त है।'उन्होंने यह तो नहीं कहा कि, वह 'बार–बार बदल जाने वाले अमेरिकियों की तरह नहीं है' लेकिन इसका साफ आशय यही था।

निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका और पाकिस्तान के हाल के तनाव से ही पहली बार पाकिस्तान चीन के करीब गया है। *द फाइनेंशियल टाइम्स* के एक बेहतरीन लेख में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य और राजनीतिक रिश्ते गहरे करने के लिए लगातार कई बार प्रयास किए हैं जैसे–कई संवेदनशील नदियों पर बांध बनाने, अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह पर चीन द्वारा निर्माण कार्य, पाकिस्तान को सैन्य साजोसामान की बढ़ती बिक्री और भारतीय सेना का यह दावा (शायद भारत के लिए सबसे संवदेनशील मसला) कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ भारत–पाक नियंत्रण रेखा के करीब चीनी सेना की मौजूद है। इन सबका अमेरिका

उन्होंने दक्षिण एशियाई हस्ती (भारत) से आग्रह किया कि वह अपना प्रभाव अपने आसपास के देशों के अलावा और दूर तक बढ़ाए खासकर पूर्वी एशिया में जहां चीन ने क्षेत्रीय राजनीति पर अपना दबदबा कायम कर रखा है।

(1) (2)

(10)

कैमरे की आंख

1 वेरिजोन सेंटर में परमपावन दलाई लामा के साथ दर्शकों का अभिभावदन करते श्री
2 पूर्वी तिब्बत के 100 से ज्यादा मठों के भिक्षु एवं भिक्षुणी 15 से 25 जुलाई, 2011 त
पर जुटे।
3 पूर्वी तिब्बत में एक विशाल धार्मिक सभा में परमपावन दलाई लामा के आदमकद चि
करते हुए इस समारोह में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए।
4 बढ़ती खाद्य कीमतों से चीन में नागरिक अशांति की आशंका बन गई है।
5 ज्युरिख में 20 जुलाई, 2011 को एक पुल पर तिब्बती भिक्षु का पुतला लटकाया ग
गायब हो चुके हैं।
6 तिब्बत के कार्जे में 6 जुलाई को सांगसोल समारोह के साथ ही परमपावन दलाई
7 चीन द्वारा आधिकारिक रूप से गैर बाध्यकारी 17 बिंदुओं वाले समझौते की 60वीं व
उनके समर्थकों ने धर्मशाला में एक 'ब्लैक मार्च' का आयोजन किया।
8 गत 16 जुलाई, 2011 को व्हाइट हाउस के मैप रूप में परमपावन दलाई लामा से
9 वाशिंगटन डीसी में पंचेन लामा फोटो प्रदर्शनी में हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे और त
10 धर्मशाला स्थिति अपने निवास से 4 जनवरी, 2010 को तीन चीनी बुद्धिजीवियों के
की फाइल फोटो।

(9) (8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

‍मरे की आंख से

‍भिभावदन करते श्री अरुण गांधी (बाएं) और श्री मार्टिन लूथर किंग तृतीय।
25 जुलाई, 2011 तक खम लिथांग गोनछेन में आयोजित चौथे जांग गुंछो छेनमो के अवसर

‍ामा के आदमकद चित्र का राज्याभिषेक किया गया। चीन सरकार के आदेश की अवज्ञा

‍न गई है।
पुतला लटकाया गया, यह दर्शाने के लिए कि तिब्बत के नाबा में कीर्ति मठ से 300 भिक्षु

‍ परमपावन दलाई लामा का जन्म दिन मनाया गया।
समझौते की 60वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने की घोषणा का विरोध कर रहे तिब्बतियों एवं
किया।
‍वन दलाई लामा से मुलाकात करते अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा।
‍टर रिचर्ड गेरे और टाशी लुल्हपो मठ के प्रमुख काछेन लोबजांग सेतान।
‍नी बुद्धिजीवियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते परमपावन दलाई लामा

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

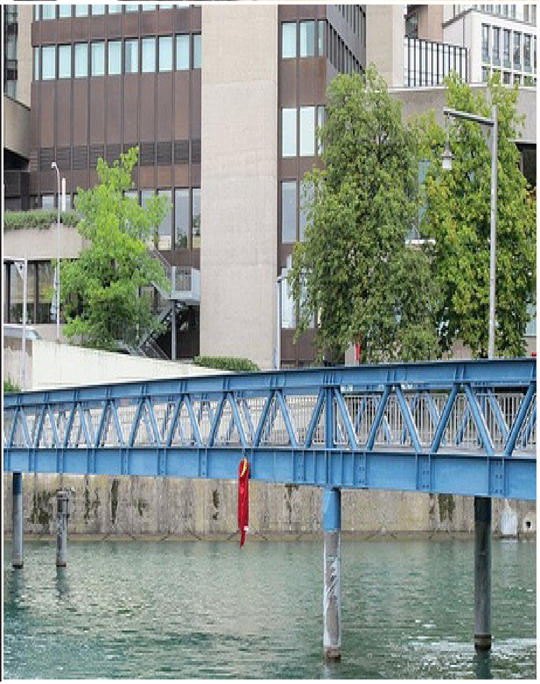

(7)

(6)

हालांकि, अपनी इस नीति से चीन ने कहीं न कहीं यह साबित करने की कोशिश की कि अरुणाचल प्रदेश 'विवादित क्षेत्र' है।

–पाकिस्तान के भविष्य के रिश्तों पर गहरा असर होगा और अमेरिका पर कम निर्भर पाकिस्तान भारत को काफी अधीर कर सकता है।चीन अब नेपाल में भारतीय प्रभाव का साफतौर पर प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ा हो गया है और उसने तिब्बत में सीमा रेखा के समानांतर बड़े राजमार्ग तैयार किए हैं। यही नहीं, वह तिब्बत के अपने रेल नेटवर्क को बढ़ाकर काठमांडू तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी बांग्लादेश की है जहां चीन चटगांव में एक गहरे जल का बंदरगाह बनाने में मदद कर रहा है। इधर भारत के पीठ पीछे श्रीलंका में चीन सबसे बड़ा सहायता देने वाला देश हो गया है और वह हमबंतोता में एक नया विशाल बंदरगाह बनाने में मदद कर रहा है। उधर बर्मा में पश्चिम के दबाव में आकर भारत ने सैन्य जुंटा के खिलाफ सख्ती दिखाई है जिससे वहां चीन ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। भारत वैसे तो अमेरिका के ज्यादा नजदीक हो रहा है, लेकिन वह अपने को धीरे–धीरे चीन से घिरता देखकर निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। अमेरिका जबकि भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है, वह खुद तमाम तरह की आर्थिक और सैन्य तंगी का सामना कर रहा है जिसकी वजह से दक्षिण एशिया में उसके प्रभाव डालने की गुंजाइश कम हो जाती है। दुनिया भर में कुल हथियार खरीद का करीब 9 फीसदी हिस्सा भारत में आता है और वह साल–दर–साल अपने रक्षा बजट में करीब 11 फीसदी की बढ़त कर देता है। चिंतित भारत सरकार को आगे भी ऐसा करते रहना पड़ेगा।

हिलेरी क्लिंटन ने कहा, एशिया का नेतृत्व करे भारत

भारतीय अधिकारी इस मामले में भ्रमित दिख रहे हैं कि चीन के इस नवीनतम कदमों को किस तरह से देखा जाए

(20 जुलाई, एबीसी न्यूज)

'यह नेतृत्व करने का समय है', अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने चेन्नई में एक भाषण में कहा। उन्होंने दक्षिण एशियाई हस्ती (भारत) से आग्रह किया कि वह अपना प्रभाव अपने आसपास के देशों के अलावा और दूर तक बढ़ाए खासकर पूर्वी एशिया में जहां चीन ने क्षेत्रीय राजनीति पर अपना दबदबा कायम कर रखा है। क्लिंटन ने कहा, "भारत के नेतृत्व से एशिया–प्रशांत के सकारात्मक भविष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। इस वजह से ही अमेरिकी सरकार भारत के पूरब की ओर देखो नीति का समर्थन करती है और भारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि न सिर्फ पूरब की ओर देखें बल्कि वहां की गतिविधियों से जुड़ें और सक्रियता से काम करें।" हालांकि, उन्होंने इस इलाके में चीनी प्रभुत्व खत्म करने के बारे में साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन उनके बार–बार यह दोहराने से यह बात साफ हो जाती है कि भारत को इस इलाके में अपने मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। क्लिंटन ने 'दुनिया में भारत के बढ़ते नेतृत्वकारी भूमिका' की चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य 'दूसरों को खुलापन और सहिष्णुता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।' चीनी ताकत के बढ़ने के युग में भारत को मजबूत करने का विचार कोई नया नहीं है। साल 2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने भारत के साथ एक नागरिक परमाणु समझौता करने का निर्णय लिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इससे भारत एक क्षेत्रीय ताकत बनेगा और एशिया में चीनी प्रभुत्व को कम कर सकेगा। शायद इसी वजह से मौजूदा राष्ट्रपति ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया है। चेन्नई में क्लिंटन का यह भाषण कोई अकस्मात नहीं है।वह इस शहर को पूर्वी एशिया में भारत की ऐतिहासिक भूमिका के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करती हैं। क्लिंटन ने कहा, "इस बंदरगाह शहर में बंगाल की खाड़ी और उससे भी आगे पूर्वी एवं दक्षिण–पूर्वी एशिया पर नजर डालते हुए हमें आसानी से इस समूचे व्यापक क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक भूमिका याद आती है। हजारों साल से भारतीय व्यापारी इस खाड़ी के जल को पार कर दक्षिण–पूर्वी एशिया और उससे भी आगे जाते रहे हैं। क्लिंटन ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका जल्दी ही भारत, जापान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा। चीन का प्रभुत्व कम करने में जापान भी अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। क्लिंटन के साथ इस भारत दौरे में अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भी आया था जो नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ नवीनतम सामरिक वार्ता करेगा। इस तरह की वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नागरिक परमाणु समझौते को लागू करने के कुछ बिंदुओं पर मतभेद की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सख्ती आ गई थी। अमेरिका ने भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वह भारत में अमेरिकी कंपनियों द्वारा परमाणु सामग्री बेचने के लिए जरूरी छूट दे। इसके पहले अमेरिका ने भारत के परमाणु सामग्री हासिल करने के रास्ते में मुश्किल खड़ी की थी क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। लेकिन भारत ने भी कई ऐसे प्रतिबंध लगाए थे जिससे फ्रांस और रूस की सरकारी कंपनियों को फायदा और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता। नई दिल्ली में क्लिंटन के हालिया दौरे में इन मसलों पर चर्चा हुई।

चीनी वीजा नीति से रिश्तों में खटास आने की संभावना

(द हिंदू, 22 जुलाई)

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने गत 21 जुलाई को इस बात पर गुस्सा और आश्चर्य जाहिर किया है कि राज्य की एक कराटे टीम जो कि चीन जा रही थी, उसे गत 19 जुलाई को नई दिल्ली में उड़ान भरने से रोक दिया गया क्योंकि उसके सदस्यों को चीनी दूतावास ने नत्थी

वीजा जारी कर दिया था। इससे चीन की वीजा नीति का दोहरापन फिर से उजागर हो जाता है जिसका साया हाल के महीनों में द्विपक्षीय संबंधों पर मंडरा रहा है। पिछले साल भारत ने तब सैन्य अधिकारियों के आवाजाही के एक कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, जब चीन ने एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को वीजा देने से मना कर दिया, इसके लिए चीन ने जम्मू–कश्मीर के भारतीय नागरिकों के लिए अपनी नत्थी वीजा नीति का हवाला दिया। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में बना गतिरोध पिछले महीने तब खत्म हुआ, जब भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीन अपनी नीति को वापस लेने को तैयार दिखता है। हाल के महीनों में चीन ने जम्मू–कश्मीर के आम नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को अपने यहां आने के लिए नियमित वीजा जारी करना शुरू किया है। लेकिन जनवरी माह में जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को नत्थी वीजा देना शुरू कर दिया, तो फिर से इस बारे में भ्रम की स्थिति हो गई कि चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में किस तरह की वीजा नीति अपनाता है। चीन के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ''सभी विवादास्पद क्षेत्रों'' के लिए नत्थी वीजा जारी करने की नीति कायम है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास अरुणाचल प्रदेश की कराटे टीम को नियमित वीजा देने को राजी हो गया है। यह टीम चीन के दक्षिणी फुजियान प्रांत के क्वांगझू शहर में आयोजित कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही थी। हाल के वर्षों में सबसे पहले साल 2007 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा देने से इनकार करना शुरू किया। उसका कहना था कि वह समूचे अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिण तिब्बत' मानता है, इसलिए वहां के लोगों को चीन यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। इसलिए चीन ने जब नत्थी वीजा देना शुरू किया तो भारतीय अधिकारियों ने माना कि इसे चीन की नीति में कुछ नरमी ही माना जाएगा, न कि सख्ती। हालांकि, अपनी इस नीति से चीन ने कहीं न कहीं यह साबित करने की कोशिश की कि अरुणाचल प्रदेश 'विवादित क्षेत्र' है। भारतीय अधिकारी इस मामले में भ्रमित दिख रहे हैं कि चीन के इस नवीनतम कदमों को किस तरह से देखा जाए, क्या ये योजनाबद्ध तरीके से दिए जा रहे संकेत हैं जो सीमा संबंधी दावों पर चल रही वार्ताओं को देखते हुए है या यह निचले स्तर की अफसरशाही द्वारा उठाए गए गैर इरादतन कदम हैं जो कि समन्वय की कमी की वजह से है।

चीन का नेपाली सीमा पर प्रभाव बढ़ा
(रिपब्लिका, 27 जुलाई)
कनक मणि दीक्षित

पेईचिंग (चीन) नेपाल की राजनीतिक घटनाओं पर जिस तरह अपना प्रभाव कायम करने की इच्छा रखता है वह सिर्फ बाजार पहुंच का मामला नहीं हो सकता। राजनीतिक रूप से चीन अपने इस पड़ोसी देश की लगातार अस्थिर राजनीति से चिढ़ा हुआ है जो उसके संवदेनशील तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) से सटा हुआ है। भू–राजनीतिक रूप से अब ऐसा लगता है कि चीनी रणनीतिकारों ने अब नेपाल को उस दक्षिण एशियाई पहुंच का हिस्सा और खंड बनाने का निर्णय लिया है जिसके तहत बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। चीन के लिए आर्थिक, राजनीतिक और भू–राजनीतिक अनिवार्यता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन पेइचिंग जो कुछ भी कर रहा है उससे लगता है कि नेपाल की राजनीतिक वास्तविकताओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को कम करके आंका जा रहा है। आधुनिक काल के नेपाल–चीन संबंधों का सांचा मार्च 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बी.पी. कोइराला और चीनी नेता माओत्से तुंग एवं चाउ एनलाई के बीच बैठक में तैयार किया गया था। तब चीन इस बात पर राजी हुआ था कि वह नेपाल को भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। पिछले कुछ दशकों से चीन एक तटस्थ पड़ोसी बना रहा जिसका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि नेपाल अपनी जमीन का इस्तेमाल 'चीन विरोधी, तिब्बत की आज़ादी' की गतिविधियों के लिए न करने दे। पेइचिंग ने नई दिल्ली के मुकाबले जो विवेकशील संतुलन कायम रखा उससे नेपाली राजनय को फायदा हुआ। चीन ने पहले कभी भी 'एक चीन' नीति और 'तिब्बत की आज़ादी' की गतिविधियों को लेकर नेपाल से कोई आश्वासन नहीं मांगा है, लेकिन इस समय अव्यवस्थित हालात को देखते हुए चीन जिस तरह से नेपाल की कमजोर सरकार पर दबाव बना रहा है उससे सीमा पर हस्तक्षेपवाद का दौर शुरू हो गया है। वास्तव में नेपाल पर चीन की आक्रामक नीति की वजह कहीं से भी काठमांडू प्रशासन के किसी कार्य या चूक को नहीं माना जा सकता। ज्यादातर इसकी वजहें चीन के मुख्य भूमि, आंतरिक मंगोलिया के सीक्यांग और तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (जहां फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार साल 2010 में विरोध प्रदर्शन की 2,80,000 घटनाएं हुईं) में विद्रोह की चिनगारियों की उसकी अपनी समस्याएं हैं। चीन अपनी असुरक्षा की भावना नेपाल तक भेज रहा है और नेपाल से वह करवाया जा रहा है जो भेदभावपरक है, जैसे शरणार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा रही है, हिमालय सीमा पर बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है और निस्तेज काठमांडू सरकार से बार–बार निष्ठा प्रकट करने की मांग जा रही है। नेपाल–चीन के द्विपक्षीय रवैए में बदलाव का दौर साल 2008 के पेइचिंग ओलंपिक से ही शुरू हो गया, जब काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे तिब्बती भिक्षुओं की तस्वीरों ने कुछ हद तक विश्व मंच पर चीन के 'आगमन' के प्रयासों को धूमिल कर दिया। इससे चीन छुइमुई हो गया और काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की सक्रियता बढ़ गई।

"लेकिन बिना आज़ाद न्यायपालिका या मुक्त प्रेस के पूंजीवाद के काफी बुरा प्रभाव–भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है। बिना किसी पारदर्शिता के चीन की बढ़ती ताकत ने उसके पड़ोसियों में डर और संदेह कायम किया है। वे हमेशा ही यह कहते रहे हैं कि उनका विस्तार का कोई इरादा नहीं है।

"दुश्मनी और संदेह से भी दयालुता से मिलो। अपने प्रिय के अलावा अन्य लोगों की मदद करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है।" करीब 21 लाख लोगों तक पहुंचा और यह सूची बढ़ती जा रही है।

आज हालत यह है कि तिब्बत से आने वाले तीर्थ यात्रियों–शरणार्थियों को धर्मशाला तक सुरक्षित रास्ता देने का समझौता पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और चीनी दूतावास हमारे गृह मंत्रालय पर दबाव बना रहा है कि दलाई लामा के जन्म दिन पर होने वाले समारोहों पर रोक लगाई जाए और जो तिब्बती ऊंचे दर्रों को पार कर नेपाल में आए हैं उन्हें कैद किया जाए या अमानवीय रूप से वापस चीन में धकेल दिया जाए। चीन इस तथ्य से असंवेदनशील दिखता है कि नेपाल का तिब्बत के साथ रिश्ता हजारों साल पुराना है और इन दोनों हिमालयी देशों में वज्रयान बौद्ध और बोन पो धर्म का पालन किया जाता है। सीमावर्ती भोटिया या हिमाली समुदाय को काठमांडू सरकार ने पूरे इतिहास में हाशिए पर रखा है और उनकी कोई सामूहिक आवाज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल उनके धार्मिक विश्वास या सीमा के आर–पार आवागमन जैसी संवेदनशीलता का ध्यान न रखे। निश्चित रूप से चाहे आक्रामक हो या परोपकारी चीनी राजनय सिर्फ चीन का हित साधने के लिए है न कि नेपाल का। कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि नेपाल के मामले में चीन की 'पहले स्थिरता' की नीति क्या पर्याप्त सोची–समझी और व्यापक है, यह देखते हुए नेपाल के आधुनिक इतिहास और बहुल जनसंख्या की वजह से इसके भविष्य के लिए लोकतंत्र से कम और कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दूसरे शब्दों में कहें तो एक अतिवादी पार्टी के नेतृत्व में शुद्ध एकाधिकारवाद लाने की अभिलाषा जरूर की जा सकती है, लेकिन कोई भी नेपाल के खुले समाज (जो कि विकास, प्रगति और स्थिरता का हमारा फॉर्मूला है) को पीछे नहीं धकेल सकता। जो कुछ हो रहा है, उससे आमतौर पर तो हमें इस बात का पर्याप्त भरोसा नहीं हो पा रहा है कि चीनी रणनीतिकारों को नेपाल के इतिहास और समाज की समझ और समानुभूति है, जबकि वे नेपाल में सत्ता की डोर थामते दिख रहे हैं।

(लेखक नेपाल के पत्रकार और लेखक हैं, हाल में उनकी पुस्तक 'पीस पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल' हिमाल बुक्स से प्रकाशित हुई है)

दलाई लामा से क्यों डरता है चीन

इस बांध का बनना कोई छोटी बात नहीं है,

(वाशिंगटन पोस्ट, 15 जुलाई)

"यदि चीन रातोरात लोकतांत्रिक प्रणाली अपना ले तो मुझे इस पर कुछ आपत्ति होगी। यदि केंद्रीय सत्ता ढह जाए तो काफी अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी और यह किसी के हित में भी नहीं होगा।" चेतावनी के ये शब्द ऐसा लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता के हैं जो फिर से पश्चिमी देशों को यह उपदेश दे रहे हैं कि वे मानवाधिकारों पर बहुत ज्यादा सख्त रवैया न अपनाएं। लेकिन नहीं, यह कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी माने जाने वाले निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा के शब्द हैं जो गुरुवार को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का पक्ष ले रहे थे कि चीन में बदलाव धीरे–धीरे होना चाहिए।

चीन में कदम–दर–कदम लोकतंत्रीकरण के उनके इस संतुलित, समझदारी भरे तर्क से यह असंभव है कि कोई चीन की इस आशंका पर अचरज न करे कि 76 साल के बौद्ध नेता उसके लिए नैतिक खतरा हैं। इससे उन्होंने ओबामा प्रशासन की दुविधा और बढ़ा दी है जो एक बार फिर इस साधारण सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्या वाशिंगटन में दलाई लामा के दस दिवसीय दौरे के दौरान उनकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात होगी। साल 1935 में जन्मे और 1959 में कम्युनिस्ट चीन से निर्वासित होकर भारत जाने वाले दलाई लामा का नजरिया काफी दीर्घकालिक सोच वाला है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि 1949 में सत्ता में आने वाले कम्युनिस्ट ऐसे सिद्धांत पर काम करते हैं जो 'जनता के लिए समर्पित हैं' लेकिन माओत्से तुंग ने जिस तरह से विचारधारा पर जोर दिया उससे यह बात अव्यवहारिक साबित हुई। नीतियों की चतुर व्याख्या से करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो गए और माओ के उत्तराधिकारी देंग जियोपिंग ने यह स्वीकार किया कि चीन को अब पूंजीवाद अपनाना होगा और लोगों को अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने की छूट देनी होगी। इसलिए आज का चीन माओ के चीन से पूरी तरह से अलग है। वहां की अर्थव्यवस्था फल–फूल रही है और दुनिया के साथ जुड़ गई है। आज हजारों चीनी विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं। दलाई लामा ने कहा, "लेकिन बिना आज़ाद न्यायपालिका या मुक्त प्रेस के पूंजीवाद के काफी बुरा प्रभाव–भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है। बिना किसी पारदर्शिता के चीन की बढ़ती ताकत ने उसके पड़ोसियों में डर और संदेह कायम किया है। वे हमेशा ही यह कहते रहे हैं कि उनका विस्तार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं अपने चीनी दोस्तों से कहता रहा हूं कि यदि सब कुछ पारदर्शी और खुला हो तो यह कहने की जरूरत ही नहीं होगी। और किसी देश में यदि सब कुछ गुप्त तरीके से होता हो तो हजार बार ऐसे इरादे को नकारें, फिर भी कोई आप पर विश्वास नहीं करता।" उन्होंने कहा कि अमेरिका और अन्य मुक्त देशों का यह अधिकार है कि वे चीन के साथ व्यापार करें और उसे वैश्विक व्यापार की मुख्य धारा में ले आएं। "अब मुक्त दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि चीन को वैश्विक लोकतंत्र की मुख्य धारा में ले आएं।" लेकिन उन्होंने कहा कि समझदारी इसी में होगी यह क्रमिक प्रक्रिया में हो, आंतरिक सेंसरशिप को खत्म करने के लिए पहले कानूनी सुधार किए जाएं।

करीब आधा सदी के निर्वासित जीवन के बाद भी दलाई लामा के आशावाद पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि अब चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ ने भी राजनीतिक सुधार की जरूरत बताया है, दलाई लामा ने कहा कि बुद्धिजीवी और पार्टी के सदस्य मौजूदा व्यवस्था के विरोधाभासों को समझते हैं। वहां निश्चित रूप से चीजें बदलेंगी।

चीन से निर्वासित होकर आ रहे छह तिब्बतियों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया

(फायूल, 13 जुलाई)

नेपाली पुलिस ने डोलाखा सीमावर्ती जिले से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे छह तिब्बतियों को गत 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। एक नेपाली समाचार एजेंसी ने डोलाखा जिला पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि 16 से 27 साल के सभी तिब्बती लड़के हैं और उन्हें आव्रजन अधिकारियों को सौंप दिया गया है। नेपाल के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि संभवतः इन तिब्बतियों को 14 जुलाई तक रिहा कर उन्हें तिब्बती स्वागत केंद्र को सौंप दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और नेपाल सरकार के बीच हुए 'जेंटलमैन समझौते' के तहत तिब्बत से आने वाले तिब्बती शरणार्थियों को भारत तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की है। लेकिन सच तो यह है कि तिब्बत से जान बचाकर नेपाल में घुसने वाले तिब्बतियों को कई बार नेपाली सुरक्षा बल पकड़ लेते हैं और उन्हें वापस चीन प्रशासन को सौंप देते हैं। पिछले साल मार्च में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की थी कि नेपाल प्रशासन अवैध रूप से अपनी सीमा में घुसने के आरोप में जिन तिब्बती शरणार्थियों को चीनी प्रशासन को सौंप देती है उन्हें वहां भारी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस साल विकीलीक्स द्वारा किए गए एक खुलासे से पता चला है कि नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे तिब्बतियों को रोकने वाले नेपाली सुरक्षा अधिकारियों को चीन ने पुरस्कृत किया है। इस साल 22 फरवरी को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की एक गोपनीय राजनयिक केबल में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "चीन सरकार ने ऐसे नेपाली सुरक्षा कर्मियों को वित्तीय प्रोत्साहन जैसे पुरस्कार दिए हैं जो चीन से आने वाले तिब्बतियों को पकड़ कर उन्हें सौंप देते हैं।" नेपाल और तिब्बत की 1,414 किलोमीटर साझा सीमा है जिस पर 34 बड़े दर्रे हैं। हर साल इन दर्रों से होकर हजारों तिब्बती तिब्बत में चीनी शासन से आज़ाद होकर निर्वासित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आती दिख रही है क्योंकि चीन सरकार के प्रयास से अब चीन–नेपाल सीमा के दोनों तरफ सख्त निगरानी की जाती है।

तिब्बत के बारे में भारत को ज्यादा मुखर होना चाहिए: करमापा

(पीटीआई, 30 जुलाई)

करमापा ओग्येन त्रिनले दोर्जी ने कहा कि तिब्बतियों के राजनीतिक एवं पर्यावरणीय अधिकारों के बारे में भारत को ज्यादा मुखर होना चाहिए। तिब्बती बौद्धों की सबसे ज्यादा सम्मानित हस्तियों में से एक 17वें करमापा ने कहा, "भारत के लिए यह अनुपयुक्त नहीं होगा कि वह इस बारे में खुद आवाज़ उठाए और इस चर्चा में बहुत सक्रिय भूमिका निभाए।" उन्होंने कहा कि भारत को तिब्बत के लिए 'सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कोई और देश' नहीं माना जा सकता, तिब्बत की संस्कृति भारतीय संस्कृति ही है।उन्होंने कहा, "अब हम यह देख रहे हैं कि तिब्बत का पर्यावरण काफी नाजुक दशा में पहुंच गया है। चीन सरकार साल 2008 से ही लगातार अपनी दमनात्मक कार्रवाई जारी रखे हुए है।

करमापा ने कहा कि तिब्बती कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, बल्कि वे अपने बुनियादी अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म पालन की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2008 के बाद दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए करमापा ने ब्रह्मपुत्र के मध्यम प्रवाह पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध के बारे में भी चेताया। उन्होंने कहा, "इस बांध का बनना कोई छोटी बात नहीं है, इसका भारत और इसके पड़ोसी देशों पर असर होगा। इस मामले पर भारत सरकार के लिए कुछ बोलना बहुत जरूरी है। करमापा तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ वाशिंगटन डी.सी. के दौरे पर हैं जो कालचक्र समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए हैं।

"हम लुंबिनी के विकास से जुड़े प्रत्यक्ष पक्ष हैं लेकिन हमें इस एमओयू की जानकारी मीडिया से मिल रही है।"

दलाई लामा ऑनलाइन भारतीयों के लिए सबसे प्रभावशाली हस्ती

(फायूल, 29 जुलाई)

दुनिया की प्रमुख मार्केटिंग कंपनी पिनस्टोर्म द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दलाई लामा को ऑनलाइन भारतीयों ने सबसे प्रभावशाली हस्ती माना है। इस मामले में दलाई लामा फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, क्रिकेट के स्टार सचिन तेंदुलकर और अरबपति उद्योगपति विजय माल्या से भी आगे निकल गए हैं।पिनस्टोर्म द्वारा जारी शीर्ष 'इंडिया इनफ्लुएंसर्स' सूची पिछले कुछ महीनों में करीब 1500 भारतीयों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखकर तैयार की गई है। किसी व्यक्ति पर किसी हस्ती के प्रभाव को मापने के लिए क्लाउट और पीयरइंडेक्स जैसे दो अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त टूल का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों टूल में मान के लिए कई जटिल सेट होते हैं और किसी व्यक्ति की सामाजिक पहुंच, स्थिति, विस्तार और गतिविधि के आधार पर गणना की जाती है। परमपावन दलाई लामा की टीम द्वारा ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की तारीफ करते हुए पिनस्टोर्म ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता अविवादित रूप से भारत में नंबर एक पायदान पर हैं और वह आश्चर्यजनक रूप से नंबर दो पायदान पर काबिज लोकप्रिय सिनेमा स्टार शाहरूख खान से आठ अंक आगे हैं।परमपावन दलाई लामा के ट्विटर और फेसबुक एकाउंट के माध्यम से दुनिया भर में 40 लाख अनुयायी हैं। उनका हाल का ट्विट, "दुश्मनी और संदेह से भी दयालुता से मिलो। अपने प्रिय के अलावा अन्य लोगों की मदद करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है।" करीब 21 लाख लोगों तक पहुंचा और यह सूची बढ़ती जा रही है।

"राजनीतिक रूप से हमारा भारत से यह विनम्र निवेदन है कि भारत को चीन के साथ वार्ता के समय तिब्बत को प्रमुख मसलों में से एक रखने के बारे में विचार करना चाहिए।"

नेपाल ने चीन के साथ लुंबिनी समझौते से इनकार किया

कुछ व्यावहारिक सोच दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अगले 50 साल में एक मजबूत और सतत तिब्बती आंदोलन की बुनियाद रखना उनकी प्राथमिकता होगी।उन्होंने कहा, "तिब्बत मसले को जिंदा रखना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है।

(द हिंदू, 29 जुलाई)
नेपाल सरकार ने एक चीनी फाउंडेशन द्वारा लुंबिनी के विकास के लिए पहल का 'सैद्धांतिक रूप से' स्वागत किया है, लेकिन उसका कहना है कि इस संबंध में कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। चीन के सरकार समर्थित फाउंडेशन दि एशिया-पैसिफिक एक्सचेंज एंड कल्चरल फाउंडेशन (एपीईसीएफ) ने घोषणा की है कि वह लुंबिनी क्षेत्र के विकास के लिए 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी।पेइचिंग में एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस पर उन्हें नेपाल की सभी राजनीतिक ताकतों 'दक्षिणपंथी एवं वामपंथी' का समर्थन हासिल है। नेपाली प्रधानमंत्री के विदेशी नीति के सलाहकार मिलन मणि तौधार ने इस खास मामले की चर्चा से बचते हुए कहा, "लुंबिनी के विकास के किसी भी प्रयास का हम सिद्धांततः स्वागत करते हैं, लेकिन उपयुक्त सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय और लुंबिनी के मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर करना होगा।" हालांकि, ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन ने इस मंजूरी के लिए किसी सरकारी माध्यम से सरकार को जानकारी नहीं दी है। नेपाल की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता दुर्गा भट्टाराई ने एक स्थानीय अखबार से कहा, "नेपाल सरकार ऐसे समझौते पर कुछ नहीं कर सकती जिसमें मेजबान सरकार को पूछा ही न गया हो।"नेपाल के संस्कृति मंत्री के प्रवक्ता मोध राज दोतेल ने कहा, "हम लुंबिनी के विकास से जुड़े प्रत्यक्ष पक्ष हैं लेकिन हमें इस एमओयू की जानकारी मीडिया से मिल रही है।" दोतेल उस एमओयू की चर्चा कर रहे थे जो फाउंडेशन और एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के बीच हुआ है।

एक उच्च पदस्थ सूत्र ने 28 जुलाई को बताया, "यह काफी रहस्यमय है।अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक हमने राजनयिक कारणों से चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लुंबिनी का विकास जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक पवित्र स्थान में इतनी बड़ी परियोजना का पूरी तरह से स्वामित्व किसी विदेशी फाउंडेशन को कैसे सौंप सकते हैं।यदि नेपाल भगवान बुद्ध की *जन्मभूमि* रही है, तो भारत उनकी *कर्मभूमि*। ऐसी परियोजना के लिए हर पक्ष को साथ में लेना होगा।" सूत्रों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल को बताया है कि वह लुंबिनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी मां को वचन दिया है जो बौद्ध थीं और वह इस संबंध में जल्दी ही नेपाल का दौरा करेंगे। श्री बान ने नेपाल सरकार को बताया है कि लुंबिनी इलाके के विकास का जिम्मा यूनेस्को को सौंपा जा सकता है। लेकिन चीन के फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ एक समझौता किया है, जिसके बारे में नेपाल सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई है। बान ने नेपाल सरकार को बताया है कि इस इलाके विकास का जिम्मा यूनेस्को को दिया जाएगा, लेकिन फाउंडेशन ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी जानकारी नेपाल सरकार को अभी तक नहीं दी गई है।

तिब्बत में हजारों लोगों ने दलाई लामा के चित्र का राज्याभिशेक किया

(फायूल, 28 जुलाई)
पूर्वी तिब्बत में एक धार्मिक समारोह में जुटे करीब 5000 लोगों ने चीन सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया और पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ परमपावन 14वें दलाई लामा के एक चित्र का सार्वजनिक तौर पर राज्याभिषेक किया। 15 जुलाई से शुरू होने वाले दस दिवसीय जांग गोंझो चेनमो धार्मिक सभा के दौरान खम लिथांग गोछेन में परमपावन दलाई लामा और दसवें पंचेन लामा के चित्रों का राज्याभिषेक किया गया। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य श्री अत्रुक सेतेन ने कहा कि तिब्बत के कोने-कोने से जुटे तिब्बतियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और भावनात्मक मौका था और वे ताज के सामने खाता (तिब्बती स्कार्फ) पेश करने के लिए पंक्तियों में लगे रहे। सेतेने ने बताया, "कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है जैसा कि वे साक्षात परमपावन दलाई लामा को देख रहे हों और उनका आशीर्वाद ले रहे हों। इस धार्मिक समारोह के आयोजकों ने पहले से ही स्थानीय चीनी प्रशासन को अपनी इस योजना की जानकारी दे दी थी कि समारोह में परमपावन दलाई लामा कि चित्र का राज्याभिषेक किया जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि इस धार्मिक समारोह में किसी तरह की बाधा पहुंचाई गई तो इसके बाद वहां जुटे लोगों की प्रतिक्रिया के लिए आयोजक जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वार्षिक अनुष्ठान में पूर्वी तिब्बत के करीब 100 तिब्बती मठों ने हिस्सा लिया और आयोजकों ने सरकारी आदेश की अवज्ञा करते हुए नाबा कीर्ति मठ को भी निमंत्रण भेजा था। श्री सेतेन ने बताया कि आयोजकों ने काफी कठोर नियम तय कर रहे थे ताकि वहां जुटे सभी लोग शुद्ध तिब्बती में बात करें और सभी के लिए चाहे वह चीनी अधिकारी क्यों न हों, यह अनिवार्य कर दिया था कि वे अनुष्ठान स्थल पर परंपरागत तिब्बती कपड़े पहनकर आएंगे।

चीन-भारत वार्ता में तिब्बत हो मुख्य मसलाः लोबसांग सेंगे

(एक्सप्रेस न्यूज, 31 जुलाई, नई दिल्ली)
चीन के साथ वार्ता में भारत को मुख्य मसलों में से एक तिब्बत को भी रखने पर विचार करना चाहिए। निर्वासित तिब्बती सरकार के मनोनीत प्रधानमंत्री लोबसांग सेंगे ने

यह बात कही। अगले 8 अगस्त को प्रधानमंत्री का पदभार संभालने जा रहे सेंगे ने एक इंटरव्यू में कहा, "राजनीतिक रूप से हमारा भारत से यह विनम्र निवेदन है कि भारत को चीन के साथ वार्ता के समय तिब्बत को प्रमुख मसलों में से एक रखने के बारे में विचार करना चाहिए। तिब्बत में चीनी सेना के आने से पहले काफी लंबे समय तक भारत की तिब्बत के साथ शांतिपूर्ण सीमा रही है। लेकिन अब सीमा पर और समुद्र में मौजूद आक्रामक चीनी सेना की मौजूदगी के बाद बहुत से भारतीय तिब्बत का महत्व समझने लगे हैं, जिसके बारे में हम बहुत पहले से तर्क दे रहे थे।" दार्जिलिंग में जन्मे सेंगे ने करीब 16 साल अमेरिका में बिताए हैं। उन्हें अप्रैल में तिब्बतियों का 'कालोन ट्रिपा' चुना गया। इसके पहले इस साल दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक शक्तियां त्याग कर चुने हुए नेतृत्व को सौंपने का निर्णय लिया था। वह 8 अगस्त को सुबह 9.09 बजे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। सेंगे ने कहा, "8–8 (आठ अगस्त) को चीनियों के लिए काफी शुभ माना जाता है और 9–9 को दीर्घायु का अंक माना जाता है।" क्या वह तिब्बत मसले को हल करने के लिए चीनी नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, इस सवाल पर सेंगे ने कहा कि वह किसी भी समय और कहीं भी अपने चीनी समकक्षों से मिलने को तैयार है, लेकिन चीन बदले में इसी तरह की सदाशयता दिखाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं अपने चीनी समकक्षों से कहीं भी और कभी भी मिलने को तैयार हूं। हम इस मसले का एक शांतिपूर्ण और परस्पर लाभकारी हल निकालना चाहते हैं। लेकिन इस मसले पर चीन की तरफ से हमेशा सदाशयता की कमी रही है। जब भी वे तिब्बत मसले पर बात करना चाहेंगे, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं।" हार्वर्ड लॉ स्कूल के ईस्ट एशियन लीगल स्टडीज प्रोग्राम के सीनियर फेलो रहे सेंगे अमेरिका में तिब्बत मसले पर कई सम्मेलनों का आयोजन कर चुके हैं और उन्होंने तिब्बती और चीनी दोनों तरह के विद्वानों को उसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दलाई लामा और कई चीनी विद्वानों के बीच मुलाकात कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "मैं हर स्तर पर चीनी विद्यार्थियों और विद्वानों के साथ इस तरह के संचार या संवाद को जारी रखूंगा।" 43 साल के तिब्बती नेता ने यह भी दावा किया कि इस तरह के संवादों से उन्हें यह समझने में मदद मिली है कि किस तरह से चीनी काम करते हैं और क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, "इस तरह के अनुभव यह समझने और विश्लेषण करने में मददगार होंगे कि किस तरह से चीनी व्यवस्था काम करती है और चीनी लोग क्या सोचते हैं।" प्रधानमंत्री के रूप में अपने पांच साल के कार्यकाल की प्राथमिकता के बारे में सेंगे ने कहा कि वह तिब्बतियों को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दलाई लामा तिब्बत लौट सकें। कुछ व्यावहारिक सोच दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अगले 50 साल में एक मजबूत और सतत तिब्बती आंदोलन की बुनियाद रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, "तिब्बत मसले को जिंदा रखना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वासन में सेंगे का जोर निर्वासित तिब्बतियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर होगा। उन्होंने कहा, "मैं यह चाहता हूं कि तिब्बती लोग अपनी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई को सुधारें। इससे उन्हें अच्छी नौकरियां हासिल करने में मदद मिलेगी और अपने समुदाय के प्रभावी नेता बनने में भी मदद मिलेगी।

अर्जिया रिनपोछे साल 1998 में तिब्बत से निर्वासित होकर आने के बाद अमेरिका में हैं।

अमेरिकी समिति ने ल्हासा में वाणिज्य दूतावास की स्थापना पर जोर दिया

(22 जुलाई, आईसीटी)

अमेरिकी सदन की एक समिति ने कहा है कि अमेरिका में चीन तब तक कोई नया वाणिज्य दूतावास नहीं खोल सकता जब तक वह अमेरिका को तिब्बत के ल्हासा में वाणिज्य दूतावास खोलने की इजाजत नहीं देता। समिति ने कहा है कि ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और पेइचिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में तिब्बत विभाग खोलने का प्रस्ताव है। गत 20 जुलाई, 2011 को सदन की विदेशी मामलों की समिति द्वारा पारित विदेशी संबंध अनुमोदन अधिनियम में यह बात कही गई है। तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) में सरकार संबंध के निदेशक टॉड स्टिन ने कहा, "समिति का यह कदम अमेरिकी कांग्रेस के करीब एक दशक से तिब्बत में अमेरिकी राजनयिक प्रतिनिधित्व की मजबूत इच्छा को दोहराता है। यह चीन सरकार द्वारा तिब्बत में अपनी नीतियों को बाहरी नजर पड़ने से पूरी तरह बंद रखने के रवैए की एक प्रतिक्रिया है।" रिपब्लिकन सदस्यों के बहुमत वाली समिति ने जो प्रावधान जोड़े हैं वह साल 2009 में मंजूर प्रावधानों जैसे ही हैं जब डेमोक्रेट के बहुमत वाली एक समिति ने एक प्रस्ताव मंजूर किया था। इससे साबित होता है कि अमेरिका के दोनों दलों की सोच इस मामले में एक जैसी है। इसके अलावा साल 2008 में कांग्रेस ने ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए 50 लाख डॉलर और अमेरिकी दूतावास में तिब्बत खंड के लिए 10 लाख डॉलर की राशि मंजूर की थी। यह विधेयक विदेश मंत्रालय को निर्देश देता है कि वह ल्हासा में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की कोशिश करे ताकि "तिब्बत की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को सेवा मिल सके और क्विंघई, सिचुआन, गांसू और यून्नान प्रांतों सहित समूचे तिब्बत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके।" इसमें कहा गया है कि, "जब तक ऐसा वाणिज्य दूतावास स्थापित नहीं

"तिब्बत के भीतर की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जब तक कि ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास नहीं खुल जाता।"

"यह एक धार्मिक मामला है।यह कलंक की बात है कि वे इस पर नियंत्रण चाहते हैं।"

हो जाता, विभाग चीन जनवादी गणतंत्र को अमेरिका में कोई भी नया वाणिज्य दूतावास खोलने की इजाजत नहीं दे सकता।" इस विधेयक के अनुसार पेइचिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में एक तिब्बत खंड की स्थापना की जाएगी ताकि "तिब्बत के भीतर की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जब तक कि ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास नहीं खुल जाता।"

अमेरिकी सरकार ने चीन में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए ल्हासा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। हाल में उप सहायक विदेश मंत्री डैन बायर ने भी गत 2 जून को समिति के सामने यह बात दोहराई। चीन सरकार अमेरिका के अटालांटा और बोस्टन में नए वाणिज्य दूतावास खोलना चाहती है, लेकिन उसने ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने की अभी तक इजाजत नहीं दी है। तिब्बत से सबसे नजदीक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सिचुआन प्रांत के चेंगदू में है जो ल्हासा से बांग्लादेश और नेपाल स्थिति अमेरिकी दूतावासों से भी दूर है।

दलाई लामा की सीमित भूमिका से चीनी योजना में अवरोध

दूसरी बात यह है कि इससे चीन की योजना को झटका लगा है क्योंकि वे 'अगले' दलाई लामा को तिब्बती जनता पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे।

(रेडियो फ्री एशिया, 14 जुलाई)

जानकारों का कहना है कि अपने पूर्ण राजनीतिक अधिकार चुने हुए प्रधानमंत्री को सौंपने के दलाई लामा के निर्णय ने चीन के तिब्बत पर और सख्त नियंत्रण कायम करने की दीर्घकालिक योजना में रोड़ा अटका दिया है। चीन की योजना दलाई लामा के खुद के प्रायोजित 'अवतार' के द्वारा तिब्बत पर और कठोर नियंत्रण कायम करने की है। गौरतलब है कि मार्च महीने में हुए चुनाव में दुनिया भर के तिब्बतियों ने हार्वर्ड के विद्वान लोबसांग सेंगे को भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार का नया कालोन ट्रिपा या प्रधानमंत्री चुन लिया है। इसके कुछ दिनों पहले ही दलाई लामा ने घोषणा की कि वह अपने पूरे राजनीतिक अधिकार और जिम्मेदारियां चुने हुए प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। यह अधिकार कई शताब्दियों से तिब्बत के मौजूदा और पूर्ववर्ती दलाई लामाओं के पास थे। वाशिंगटन में तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान के उपाध्यक्ष भुचुंग सेरिंग ने इस हफ्ते वाशिंगटन में कहा कि दलाई लामा द्वारा राजनीतिक अधिकार त्यागने के निर्णय से चीनी नेताओं को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने संदेह जाहिर किया कि दलाई लामा अपनी इस घोषणा पर गंभीरता से पालन नहीं करेंगे। चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग द्वारा आयोजित एक गोलमेज चर्चा में सेरिंग ने कहा, "यह एक ऐसी बात थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसा कि दलाई लामा ने किया क्या कोई व्यक्ति स्वयं ही खुशी पूर्वक सत्ता छोड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि इससे चीन की योजना को झटका लगा है क्योंकि वे 'अगले' दलाई लामा को तिब्बती जनता पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब जबकि दलाई लामा ने यह कह दिया है कि वह न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि भविष्य के सभी दलाई लामाओं के लिए भी राजनीतिक अधिकार त्याग रहे हैं तो चीनियों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब वे क्या करें।" चीन सरकार ने पहले घोषणा की थी कि चौदहवें दलाई लामा के निधन पर वे खुद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इससे इस बात की संभावना गहरा गई थी कि आगे दो दलाई लामा हो जाएंगे, एक जिनकी मान्यता चीन देगा और दूसरा जो निर्वासित तिब्बतियों द्वारा माने जाएंगे।साल 1995 में दलाई लामा ने तिब्बत के एक बच्चे को दसवें पंचेन लामा का अवतार घोषित किया था। पंचेन लामा को तिब्बती बौद्ध धर्म की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती माना जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद चीनी प्रशासन ने इस बालक को नजरबंद कर दिया और उसकी जगह खुद एक दूसरे बच्चे को पंचेन लामा घोषित कर दिया। तिब्बती लोग चीन द्वारा नियुक्त पंचेन लामा को जाली मानते हैं। एसोसिएटेड प्रेस को इस माह दिए एक इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी के निर्धारण में चीनी कम्युनिस्ट नेताओं की कोई भूमिका नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, "यह एक धार्मिक मामला है। यह कलंक की बात है कि वे इस पर नियंत्रण चाहते हैं। वे राजनीतिक सत्ता पाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं।" आयोग के समक्ष इस हफ्ते बोलते हुए तिब्बत के कुमबुम मठ के पूर्व प्रमुख अर्जिया रिनपोछे ने भी इससे रजामंदी दिखाते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण लामाओं के अवतार की पहचान करने की तिब्बती परंपरा सिर्फ तिब्बतियों का मसला है। इसको अपने हिसाब से चलाने की चीन सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिनपोछे साल 1998 में तिब्बत से निर्वासित होकर आने के बाद अमेरिका में हैं।

आयोग के सामने बोलते हुए पूर्व राजनीतिक कैदी नवांग सांगड्रोल ने कहा कि दलाई लामा तिब्बतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर चीनी कैद झेल रहे तिब्बती राजनीतिक कैदियों के लिए। एक राजनीतिक कैदी और खासकर छह माह तक अकेले रखे जाने के अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर अंधेरे, ठंडे जगह पर और भूखे रखा जाता था। तिब्बत में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए सांगड्रोल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, "हर दिन मैं कल्पना करती थी कि परमपावन दलाई लामा का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। इससे मुझे काफी शांति मिलती थी, जबकि मेरी भौतिक दशा काफी भयानक थी। यही केवल एक बात थी जिससे मुझे जिंदा रहने का हौसला मिलता था। दलाई लामा न सिर्फ तिब्बतियों की इस पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे।